THE MINISTER OP STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI JANBSHWAR MISHRA); (a). The estimated cost for the first technology mission is Rs. 35 crores and the second technology mission is Rs. 32 crores. Under each mission, a number of projects are undertaken.

(b) The first mission was for 35 months and the second mission was for 31 months.

(c) The total expenditure by C-DOT upto 31-3-1989 is Rs. 56.45| crores. Expenditure for the year 19619-90 is being compiled.

(d) C-DOT has developed a family of Digital Electronic Switching Sys tems. Technology transfer for the manufacture of the following products has been effected:

(i) 128-port PARX (Private Auto-matic Branch Exchange)

(ii) 128-port RAX (Rural Automatic Exchange).

Agreements for transfer of technology for 512-Port RAX have also been entered into with ITI and 8 other manufacturers.

(e) Report of the Expert Committee constituted for assessment and evalua tion of C-DOT is under examination of the Government. Decision of the Government on the report will be placed before the Parliament after the same is finalised.

Family Pension to widows of the Victims of Terrorist Violence in Pun-jab, J&K and Delhi

*26. SHRI KRISHAN LAL' SHARMA;

SHRI VIREN J. SHAH;

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any scheme of Government to provide family pension to the widows of the victims of test rorist violence in Punjab, J&K and Delhi;

(b) it so, what is the current rate of pension payable to such widows;

(c); whether Government propose to enhance the rate of pension pass-able to such families in order to save them from destitution and to make it equal/uniform in all the States; and

(d) what other facilities Govern-ment propose to provide to the affected families?

THE MINISTER OF HOME AF FAIRS (SHRI MUFTI MOHAMMADI SAYEED): (a) to (d) According to information available the Govern-ment of Punjab have formulated package of relief for the victims of terrorist violence in the State undent which Rs. 500/- per month is payable as subsistence allowance to the widows of the victims. The Prime Minister has since announced that this amount would be raised to Rs. 1000/- per month.

No such scheme for payment of family pension to the widows of terrorist violence is in existence in the Union Territory of Delhi. Information in this regard is awaited from the Government of J&K.

गांवों में डाकघर की सुविधाओं की व्यवस्था

*27. श्री राम नरेश यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में पेश आने वाली संचार संबंधी समस्याओं को मददेनजर रखते हुए 1000 की जनसंख्या वाले गांवों में डाकघर की सुविधाएं कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है ; और

(ख) इस कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अवेश्वर सिंह) : (क) प्रचलित मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर ऐसे ग्राम समूह के लिए एक डाकघर खोला जा सकता है जिनकी जनसंख्या मिलाकर 6000 या उससे अधिक हो :

(i) किसी मौजूदा डाकघर से 3 कि०मी० की दूरी के भीतर कोई नया डाकघर नहीं खोला जा सकता।

(ii) डाकघर की अनुमानित आय उसकी अनुमानित लागत से 33.1/3 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

जहां तक पहाड़ी इलाकों और पिछड़े/जनजातीय इलाकों का संबंध है, उनकी मिली-जुली जनसंख्या कम से कम 1500 होनी चाहिए और डाकघर की अनुमानित आय उसकी लागत के 15 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

ऊपर उल्लिखित मानदंडों की अब पुनरीक्षा की जा रही है। जब यह पुनरीक्षा पूरी हो जाएगी, तब आठवीं योजना में अपनाए जाने वाले मानदंड निश्चित किए जाएंगे और साथ ही उन गांवों की संख्या भी निर्धारित की जाएगी जिनमें डाकघर खोले जाने हैं।

(ख) योजना आयोग ने वार्षिक योजना 1990–91 के अंतर्गत नए डाकघर खोलने के लिए 1.50 करोड़ रु० की राशि आवंटित की है।

भारतीय शान्ति सेना की वापसी

*28. **श्री राम जेठमलानी :**

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय शांति सेना की अन्तिम टुकड़ी भी 31 मार्च, 1990 को श्रीलंका से स्वदेश वापस आ गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि शांति सेना के वापस आने के साथ-साथ लगभग एक लाख तमिल शरणार्थी भी भारत आ चुके हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आज से लगभग तीन वर्ष पूर्व किए गए श्रीलंका-भारत समझौते को कार्यरूप देने में सहायता करने हेतु तथा श्रीलंका में भारतीय मूल के नागरिकों के संरक्षण हेतु भेजी गई भारतीय शांति सेना को आंशिक सफलता ही मिली है और समझौता अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) भारतीय शांति सेना के अंतिम सैनिक दल 24 मार्च, 1990 को श्रीलंका से रवाना हो गया था।

(ख) जहां तक ज्ञात है 26 अगस्त, 1989 से 24 मार्च, 1990 के बीच श्रीलंका के 4943 शरणार्थी भारत में आए थे जबकि 25 मार्च, 1990 से 4 अप्रैल, 1990 के बीच इनकी संख्या 27 थी।

(ग) और (घ) भारत-श्रीलंका समझौते का आशय यह था कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष के समाधान के लिए एक रूप-रेखा तैयार की जाए। इस दिशा में काफी प्रगति की गई है जिसमें प्रान्तीय परिषदों का गठन करना, इन परिषदों को सत्ता सौंपने के लिए संवैधानिक संशोधन करना, उत्तर और पूर्वी प्रान्तों का विलय, तमिल को राजभाषा बनाया जाना आदि शामिल है। तथापि, भारतीय शांति सेना की वापसी के के बाद तमिलों को सुरक्षा और हिफाजत प्रदान करने और जातीय समस्याओं के बकाया पहलुओं का समाधान करने की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी श्रीलंका की सरकार की है। सरकार स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए है।